

# फायर टेक्नीशियन कोर्स के फर्जी प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था का निदेशक गिरफ्तार

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को फर्जी डिग्रियां उपलब्ध करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसओजी ने फायर टेक्नीशियन, फायरमैन और लाइब्रेरियन कोर्स की बैक डेट में फर्जी डिग्रियां जारी करने वाली निजी संस्था भारत समाज सेवक (बीएसएस) इंस्टीट्यूट, चेन्नई के निदेशक अरुल ग्नाना मोइसन को गिरफ्तार किया है। आरोपी को एसओजी की टीम चेन्नई से गिरफ्तार कर जयपुर लाई है।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एसओजी) विशाल बंसल ने बताया कि राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं, विशेषकर फायरमैन और लाइब्रेरियन भर्ती में फर्जी डिग्रियों की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। जांच के दौरान भारत समाज सेवक (बीएसएस) संस्थान संदिग्ध पाया गया। प्रारंभिक स्तर पर पटवारी भर्ती से जुड़ी शिकायतों की भी जांच की गई, लेकिन वहां गड़बड़ी नहीं मिली। इसके बाद जांच का फोकस फायरमैन भर्ती पर किया गया, जहां बीएसएस



निदेशक अरुल ग्नाना मोइसन

संस्थान से बैकडेट में डिग्रियां जारी होने के ठोस सबूत सामने आए। एसओजी ने पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पृष्ठताछ के आधार पर हिंडीन (करोली) स्थित एएस फायर सेप्टी इंस्टीट्यूट के संचालक श्यामवीर को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में सामने आया कि यह संस्थान बीएसएस से एंफिलिएटेड है। इसके बाद एसओजी ने बीएसएस के चेन्नई और दिल्ली स्थित कार्यालयों की तलाशी ली, जहां बड़ी संख्या में बैकडेट में जारी की गई डिग्रियां और प्रमाण-पत्रों से

- फायरमैन और लाइब्रेरियन कोर्स की बैक डेट में फर्जी डिग्रियां जारी करने वाली निजी संस्था भारत समाज सेवक (बीएसएस) इंस्टीट्यूट, चेन्नई के निदेशक अरुल ग्नाना मोइसन को गिरफ्तार किया**

जुड़े दस्तावेज बरामद हुए। सबूत जुटाने के बाद कोर्ट से वारंट प्राप्त कर बीएसएस के निदेशक अरुल ग्नाना मोइसन को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया।

एसओजी के डीआईजी परिस देशमुख ने बताया कि जांच में स्पष्ट हुआ है कि भारत समाज सेवक (बीएसएस) संस्थान को यूजीसी या किसी भी वैधानिक संस्था से कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके बावजूद यह संस्थान वॉकेशनल कोर्स के नाम पर फायरमैन, फायर टेक्नीशियन, लाइब्रेरियन सहित कई कोर्सेज की डिग्रियां जारी कर रहा था।

जांच में सामने आया कि बीएसएस ने फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करते हुए देशभर में अपने नेटवर्क का विस्तार किया। संस्था से करीब 1० हजार इंस्टीट्यूट जुड़े, जिनमें से लगभग 7 हजार अभी सक्रिय हैं। इन

संस्थानों और दलालों के माध्यम से हजार से अधिक कोर्सेज की डिग्रियां ऑन-डिमांड जारी की जाती थीं।पड़ताल में यह भी सामने आया कि हर इंस्टीट्यूट का एक दलाल होता था, जो अभ्यर्थियों को झंसे में लेकर उनकी जानकारी बीएसएस कार्यालय भेजता था। इसके बाद मांगी गई तारीख के अनुसार बैक डेट में डिग्री और प्रमाण-पत्र जारी कर दिए जाते थे।एसओजी अधिकारियों के अनुसार आरोपी से पृष्ठताछ जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां संभव हैं।

एसओजी ने आमजन और नियोजक संस्थाओं से अपील की है कि किसी भी डिग्री या प्रमाण-पत्र के आधाार पर चयन से पहले उसका पूर्ण और विधिवत सत्यापन अवश्य करें।

## ड्रोन व पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध सरकार के प्रार्थना पत्र पर निचली अदालत करे फैसला

जयपुर। राजस्थान पुलिस अकादमी शास्त्री नगर में 1० जनवरी 2०26 को प्रस्तावित वीवीआईपी के आगमन कार्यक्रम को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। वीवीआईपी की सुरक्षा व्यवस्था को प्राविात होने की आशंका को देखते हुए पुलिस अकादमी क्षेत्र के आसपास ड्रोन और पतंग उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।

# महिंद्रा की एक्सयूवी7एक्सओ और एक्सईवी9एस का अनावरण

जयपुर। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में होटल जयपुर मैरियट में अपनी दो नई दमदार एक्सयूवी7एक्सओ और एक्सईवी9एस का भव्य लॉन्च किया। यह कारोंकम बेहद शानदार रहा, जिसमें मौजूदा और नए ग्राहकों की बड़ी संख्या ने हिस्सा लिया।

- इच्छुक ग्राहक इसे 14 जनवरी से बुक कर सकते हैं**

लॉन्च समारोह का उद्घाटन के एस मोटर्स के डीलर प्रिंसिपल के एस गहलोत, करण गहलोत व आराधना गहलोत, ऑटोवर्ल्ड के असुपम सांखला तथा निखित शाह, आरएसएम महिंद्रा एंड महिंद्रा व अन्य वरिष्ठ सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम में दोनों वाहनों का अनावरण किया गया, जिसके बाद ग्राहकों ने इनकी विशेषताओं को करीब से देखा और आनंद लिया। एक्सयूवी7एक्सओ के इस नए मॉडल की शुरुआती क्रीमव पेडोल व्हेरीएंट के लिए 13.66 लाख रुपए और डीजल व्हेरीएंट के लिे 14.96 लाख



लॉन्च समारोह का उद्घाटन के एस मोटर्स के डीलर प्रिंसिपल के एस गहलोत, आराधना गहलोत ने किया ।

रुपए रखी गई है। ये क्रीमते पहले 40,000 ग्राहकों के लिए इंट्रोडक्टरी एक्स-शोरूम हैं। नई एक्सयूवी7एक्सओ को पहले से ज़्यादा प्रीमियम डिज़ाइन, अपडेटेड केबिन और कई नए फीचर्स के साथ पेश किया गया है। इच्छुक ग्राहक इसे 14 जनवरी से बुक कर सकते हैं।

नई एक्सयूवी7एक्सओ को ग्राहक छह व्हेरीएंट्स में से चुन सकते हैं, जिसमें , 3, 5, 7, 7 और 7 शामिल हैं, जो चार इंजन ऑप्शन में आते हैं। इसके अलावा, इसे भारत एनकैप क्रैश टेस्ट

में 5-स्टार रेटिंग मिली है।

महिंद्रा की ई-एसयूवी लाइनअप में 9, 6 और 4०0 के साथ शामिल हो गया है। क्रीमव 19.95 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

महिंद्रा एक्सईवी9एस का डिज़ाइन इसे बाकी एसयूवीज़ से अलग बनाता है। इसमें एक ब्लैक-आउट ग्रिल, एल आकार के एलईडी डीआरएल्स, व्हिंकल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और प्रंट फेंशिया पर एक पिक्सल स्टायल एलईडी लाइट बार मिलता है।

- राजस्थान में 10 जनवरी से कांग्रेस का हल्लाबोल**

राजनीति में यह मुद्दा शहर से लेकर गांव की चौपालों तक चर्चा का केंद्र बना रहेगा। विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में लंबे समय से फर्जीबाड़ा और भ्रष्टाचार फल-फूल रहा था। फर्जी जाँच कार्ड सरपंचों के पास मिलते थे और मजदूरों के हक का पैसा बिचौलिया खरा रहे थे।

नए कानून के जरिए भ्रष्टाचार पर रोक लगाए हुए पारदर्शिता लाई गई है। सरकार ने रोजगार के दिन 1०० से बढ़ाकर 1२5 दिन कर दिए हैं। राठौड़ ने कहा कि आजीविका मिशन के शब्दों को जोड़ने से यदि नाम नाम बन गया, तो इस पर आपत्ति करना कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने दावा किया कि 2००4 से अन्न तक खर्च हुए कुल 11.74 लाख करोड़ रुपये में से 8.53 लाख करोड़ रुपये अकेले बीजेपी सरकार ने खर्च किए हैं।

जहां एक तरफ कांग्रेस मनरेगा बचाओं के नारे के साथ सड़कों पर उतर रही है। वहीं बीजेपी ने भी वीबी-जी-राम-जी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया है।

आने वाले दिनों में राजस्थान की



चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर द्वारा कार्यकर्ता सुनवाई आयोजित का

उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि किसी भी कार्यकर्ता की समस्या लंबित न रहे। मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने बताया कि आज की सुनवाई में करीब 150 परिवार प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश तबादलों से संबंधित थे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सुनवाई जैसे कार्यक्रम सरकार और संगठन के बीच

सेतु का कार्य करते हैं और जमीनी स्तर की वास्तविक समस्याओं को सामने लाते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार कार्यकर्ताओं की भूमिका को सर्वोपरि मानते हुए ऐसी सुनवाईयों के माध्यम से पारदर्शी एवं सेवेदनशील प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं संगठन स्तर

पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देने और संगठन को मजबूत करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। कार्यकर्ता सुनवाई में प्रदेश मंत्री नारायण मीणा भी उपस्थित रहे।

# आरपीएससी सचिव बताए नोटिस तामील के बाद भी पक्ष रखने के लिए कोई उपस्थित क्यों नहीं : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती-2024 से जुड़े मामले में आरपीएससी सचिव को 8 जनवरी को सुनवाई के दौरान वीसी से जुड़ने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि इस दौरान सचिव सभी जरूरी दस्तावेज भी साथ रखें। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश सुष्टि सिंघल व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि मामले में नोटिस जारी करने के बाद उनकी तामील में हो चुकी है, लेकिन आयोग की ओर से कोई पेश नहीं हुआ और केस के अंजोइसी भी हाज़िर नहीं हुए। ऐसे में आयोग सचिव इस संबंध में अपना उचित स्पष्टीकरण दें।

याचिका में अधिवक्ता तनवीर

## पांच आरोपित गिरफ्तार

जयपुर। चित्रकूट थाना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि इन आरोपियों को दुबई से संचालित नंबरों के माध्यम से सट्टेबाजी के लिए आईडी (लाइन) उपलब्ध करवाई जा रही थी। पुलिस अब इस मामले में दुबई कनेक्शन की भी गहन जांच कर रही है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि चित्रकूट थाना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए

अजमेर निवासी साहिल खान के साथ नागौर निवासी इब्राहिम खान, दीलत अली, इमरान खान और जाकिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके साथ एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। पुलिस कार्रवाई में आरोपियों के पास से 5० से अधिक बैंक खाते मिले हैं। जिनमें सट्टेबाजी की रकम द्वांस्फर की जा रही थी। पुलिस ने इन खातों में करीब दो लाख रुपये की रकम होल्ड भी करवा दी है।

## मनरेगा का नाम बदलने पर छिड़ा सियासी संग्राम

- राजस्थान में 1० जनवरी से कांग्रेस का हल्लाबोल**

राजनीति में यह मुद्दा शहर से लेकर गांव की चौपालों तक चर्चा का केंद्र बना रहेगा। विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में लंबे समय से फर्जीबाड़ा और भ्रष्टाचार फल-फूल रहा था। फर्जी जाँच कार्ड सरपंचों के पास मिलते थे और मजदूरों के हक का पैसा बिचौलिया खरा रहे थे।

नए कानून के जरिए भ्रष्टाचार पर रोक लगाए हुए पारदर्शिता लाई गई है। सरकार ने रोजगार के दिन 1०0 से बढ़ाकर 1२5 दिन कर दिए हैं। राठौड़ ने कहा कि आजीविका मिशन के शब्दों को जोड़ने से यदि नाम नाम बन गया, तो इस पर आपत्ति करना कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने दावा किया कि 2००4 से अन्न तक खर्च हुए कुल 11.74 लाख करोड़ रुपये में से 8.53 लाख करोड़ रुपये अकेले बीजेपी सरकार ने खर्च किए हैं।

## बकाया नगरीय विकास कर की वसूली के लिये टीम अलर्ट मोड पर

जयपुर। नगर निगम जयपुर के आयुक्त डॉ. गौरव सेनी के निर्देशनुसार मानसरोवर जोन में नगरीय विकास कर की बकाया राशि की वसूली को लेकर सख्त कार्रवाई की गई। इस क्रम में बुधवार को सिविल लाइंस जोन क्षेत्र में स्थित कुल 6 संपत्तियों पर बकाया नगरीय विकास कर की राशि की वसूली की कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई जोन उपायुक्त लक्ष्मीकांत कटारा के नेतृत्व में राजस्व अधिकारी, प्रशासनिक एवं राजस्व विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से की गई।

कार्रवाई के दौरान संपत्तियों पर बकाया राशि जमा कराने हेतु कुर्क क की प्रक्रिया अपनाई गई। जोन उपायुक्त लक्ष्मीकांत कटारा ने बताया कि कार्रवाई के दौरान राजस्व टीम द्वारा बकायदारों पर कुर्क की कार्रवाई की गई जिसमें दो संपत्तियों पर कुर्क की गई तथा शेष चार प्रकरणों में वारंट/कुर्क से पूर्व ही समझाइश के दौरान 11 लाख 71 हजार 998 रुपये बकाया नगरीय विकास कर जमा कराया गया।

इसके अतिरिक्त झोटवाड़ा, वैशाली नगर जोन में भी राजस्व शाखा द्वारा 6 सम्पत्तियों पर नगरीय विकास

राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा में चालीस फीसदी से अधिक अंक हासिल किये थे। आरजेएस परीक्षा सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा से कहीं अधिक कठिन परीक्षा मानी जाती है। इसके बावजूद ऐसे अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में असफल कर दिया गया।

याचिका में कहा गया कि आयोग की ओर से जारी यह परिणाम ममाना, अव्यावहारिक और संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है। याचिका में आशंका जताई गई है कि परीक्षा के मूल्यांकन में त्रुटिपूर्ण मॉडल उत्तर और अत्यधिक कठोर अंकन कर मपीनी अंदाज में कोर्पाय जांची गई है। ऐसे में परीक्षा परिणाम को रद्द कर नए सिरे उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर संशोधित परिणाम जारी किया जाए।

# मनरेगा पर आलाकमान की भाषा बोल रहे सीएम : टीकाराम जूली

- जूली ने कहा कि, जिस व्यवस्था ने उन्हें पहचान दी, आज उसे ही कमजोर करने में वे केंद्र का सक्रिय हिस्सा बन रहे हैं। यह सिर्फ राजनीतिक अवसरवाद नहीं, बल्कि ग्रामीण लोकतंत्र के साथ ऐतिहासिक विद्रोहसघात है। यह राजस्थान का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री स्वयं ग्रामीण परिवेश से होने के बावजूद दिल्ली के आलाकमान की भाषा बोल रहे हैं**

करने के बजाय केवल दिल्ली के संदेशवाहक बनकर रह गए हैं। जूली ने कहा कि, अब तक मनरेगा का खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, लेकिन अब इसे 6०:4० के अनुपात में बांटकर राज्यों पर 4० प्रतिशत फंड का बोझ डालना तानाशाही है। इससे राजस्थान के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और राज्य का खजाना खाली होगा। यह

सोधे तौर पर संघीय ढांचे को नष्ट करने की साजिश है। जूली ने कहा- वीबी जी राम जी केवल नाम बदलना नहीं, बल्कि मनरेगा के मूल सिद्धांतों पर हमला है। मनरेगा

एक कानूनी अधिकार था, जबकि नई योजना इसे केंद्र की मजी पर निर्भर

बनाना चाहती है। मनरेगा ने गांवों में रोजगार देकर पलायन रोका और महिलाओं को आर्थिक संबल दिया। भाजपा को गांधी और मनरेगा, दोनों खटकते हैं, इसलिए इस हक को छीनने की साजिश रची गई है।जूली ने सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री दिल्ली की कुर्सी बचाने के लिए प्रदेश के गरीब मजदूरों के हक की बलि चढ़ा देंगे?

उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस पार्टी इस निचविरोधी नीति का सदन से लेकर सड़क तक कड़ा विरोध करेगी।

### सार-समाचार

## विकसित भारत में पुलिसिंग विषय पर राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन आज से

जयपुर । विकसित भारत में पुलिसिंग विषय पर राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 8 व 9 जनवरी को राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में आयोजित किया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं निदेशक संजीव कुमार नाजरी राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने बताया कि इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजनलाल शर्मा होंगे। गृह राज्य मंत्री जगवह सिंह बेदाम, मुख्य सचिव राजस्थान वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग भास्कर ए.सावंत, उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा व जयपुर मुख्यालय पर युद्धस्थापित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तथा सभी रेंज आईजी, सभी जिला पुलिस अधीक्षक व अन्य पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा 12 जनवरी 195० को नई दिल्ली में किया गया। इसी क्रम में 6० वाँ राष्ट्रीय डीजी/आईजी पुलिस सम्मेलन नवम्बर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ। जिसकी सिफारिशों के अनुक्रम में आयोजित होने वाले इस राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन में ०2 दिन में दस सत्र आयोजित होंगे। जिनमें विकसित भारत में पुलिसिंग सम्बन्धी विषयों पर महत्वपूर्ण व्याख्यान होंगे।

## जयपुर केंद्रीय कारागार में फिर मिला मोबाइल फोन

जयपुर। घाटगेट स्थित केंद्रीय कारागार में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जेल प्रशासन द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान जेल परिसर से मोबाइल फोन बरामद होने से हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची लाल कोठी थाना पुलिस ने मोबाइल फोन जब्त कर उसके ईएमआई नंबर और सिम नंबर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जेल प्रशासन ने वार्ड नंबर-7 की बैक नंबर-3 में स्थित टॉयलेट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टॉयलेट में छुपाकर रखा गया एक की-पैड मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद हुआ। इसके बाद जेल प्रशासन ने तत्काल इसकी सूचना लालकोठी थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जेल कारापाल अशोक कुमार की रिपोर्ट पर अज्ञात बंदी के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस अब बरामद मोबाइल फोन के ईएमआई नंबर और सिम कार्ड के माध्यम से यह पता लगाने में जुटी है कि मोबाइल किस बंदी का है और जेल के भीतर यह कैसे पहुंचा।

# जल जीवन मिशन घोटाले में जांच का दायरा सीमित क्यों

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में की जा रही जांच को सिर्फ दो फर्मों तक सीमित रखने के मामले में ईडी और राज्य सरकार से जवाब देने को कहा है। एफ़िंटंग सोजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक ऑफ़ेंस करणन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पीसी भंडारी और अधिवक्ता टीएन शर्मा ने कहा कि जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था।

इसके बावजूद भी केवल दो टेका फर्म के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज

कर जांच की गई है। याचिकाकर्ता ने कई अन्य लोगों व फर्म के खिलाफ भी शिकायत दी थी, लेकिन केवल दो फर्मों के अलावा अन्य की ओर से किए गए

- याचिकाकर्ता ने कई अन्य लोगों व फर्म के खिलाफ भी शिकायत दी थी**

फर्जीबाड़े की न तो जांच की गई और ना ही अब तक एफआईआर दर्ज की गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि मामले में प्रभावशाली लोगों को बचाया जा रहा है। ईडी की ओर से एएसजी भरत व्यास ने कहा कि ईडी ने कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार भी किया है। याचिकाकर्ता की ओर से लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं।

जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के आरोपों का जवाब देने के लिए मामले को सुनवाई तीन सप्ताह बाद करना तय किया है।